PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 036
दि. 05.06.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया

योग मानवता को भारत का शाश्वत उपहार है! मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ते हुए यह एक अधिक स्वस्थ, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विश्व की प्रेरणा देता है : प्रधानमंत्री

अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर नगरी है, और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में इस आयोजन का होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है : प्रधानमंत्री

विश्व योग दिवस से पहले आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप अपने साथ स्वास्थ्य और कल्याण की दोहरी सौगात लेकर आई है : प्रधानमंत्री

इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन को ओलंपिक तथा अन्य बहु-खेल आयोजनों में भी शामिल किया जाएगा : प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अहमदाबाद से वीडियो संदेश के माध्यम से प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जो वैश्विक खेल विरासत में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। श्री मोदी ने कहा, 'आज अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक नया अध्याय जुड़ रहा है।'

इस अग्रणी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए विश्वभर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी अहमदाबाद द्वारा किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा, 'अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर नगरी है, और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में इस आयोजन का होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।'

विश्व स्तर पर आयोजित हो रहे योग उत्सवों के समागम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस विभिन्न देशों में अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जबकि इसका मुख्य कार्यक्रम भारत के एक अन्य ऐतिहासिक शहर कोलकाता में आयोजित होगा। श्री मोदी ने कहा, 'विश्व योग दिवस से पहले आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप अपने साथ स्वास्थ्य और कल्याण की दोहरी सौगात लेकर आई है।'

योग को वैश्विक पहचान दिलाने की भारत की यात्रा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि लगभग एक दशक पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन परंपरा को समस्त मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना था। श्री मोदी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।'

योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में लाखों लोगों ने योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या और जीवनशैली का हिस्सा बना लिया है। जीवंत परंपराओं के निरंतर विकासशील स्वरूप पर बल देते हुए उन्होंने विश्व योगासन चैंपियनशिप को योग के एक नए और समकालीन रूप में प्रासंगिक परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश का प्रतीक बताया।

योगासन को एक मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी खेल विधा के रूप में स्थापित करने में इस चैंपियनशिप के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में इसे

विश्व के प्रमुख खेल आयोजनों में स्थान मिलेगा। श्री मोदी ने कहा, 'इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी, और मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन को ओलंपिक तथा अन्य बहु-खेल आयोजनों में भी शामिल किया जाएगा।'

अहमदाबाद की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल जगत में मुख्यधारा की पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक खेल के रूप में योग के विकास के व्यापक आर्थिक और व्यावसायिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों और पेशों में नए अवसर उत्पन्न होंगे। श्री मोदी ने कहा, 'जैसे-जैसे योगासन खेल का विस्तार होगा, वैसे-वैसे नई संभावनाएँ भी विकसित होंगी, जिससे खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकताओं और आयोजन प्रबंधकों के लिए नए करियर अवसर सृजित होंगे।'

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं और दीघार्यु की आकांक्षा रखने वाली आधुनिक आबादी के लिए योग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, 'जो लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बने रहने के उपाय खोज रहे हैं, उनके लिए योग एक अत्यंत उपयुक्त विकल्प है।'

योग को एक ओर मुक्त कर देने वाली साधना और दूसरी ओर किफायती स्वास्थ्य समाधान बताते हुए श्री मोदी ने इसके सार्वभौमिक रूप से सुलभ होने का समग्र संदेश दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक स्मरणीय मंत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने योग की रोग-निवारक क्षमता को सरल शब्दों में व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, 'रोज योग कीजिए, और योग सभी रोगों को दूर भगा देगा।'

आयुष मंत्रालय द्वारा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए शुरू किए गए ह्ययोग 365ह्व अभियान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर व्यापक भागीदारी का आ'ान किया। उन्होंने चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से अपने-अपने देशों में लौटकर योग के वैश्विक दूत बनने की अपील की और उन्हें प्रभावशाली प्रेरक व्यक्तित्वों के रूप में रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा, 'जब आप अपने-अपने देशों में लौटें, तो योग 365 के दूत के रूप में योग का यह संदेश अपने साथ लेकर जाएँ और अपने अनुभव तथा आस्था के माध्यम से पूरी दुनिया को इस संदेश से जोड़ें।'

प्रधानमंत्री 5 जून को सूरत और दमन का दौरा करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्ेद्र मोदी 5 जून, 2026 को गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:30 बजे, सूरत जिले के हजीरा में चल रहे औद्योगिक कार्यों और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 4:15 बजे, सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री दमन के लिए रवाना होंगे, जहां शाम लगभग 6:15 बजे वे दमन स्थित नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दमन में स्थित नामो

अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। फिर सायं लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, समर्पण और शिलान्यास करेंगे। वे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

सूरत में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में फैली 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज VI और VII राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उच्च गति परिवहन, लॉजिस्टिक स दक्षता और आर्थिक संपर्क में सुधार होगा। प्रधानमंत्री प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के महत्वपूर्ण खंडों को चार लेन का बनाना शामिल है।

प्रधानमंत्री सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो प्रमुख स्पेशियलिटिज में आधुनिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही, यह एक केंद्रीय प्रयोगशाला और आवश्यक सहायक सेवाओं से भी सुसज्जित होगा। इसमें व्यावसायिक चोटों और चिकित्सा आपात स्थितियों के समय पर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 24/7 आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल की सुविधा भी है। प्रधानमंत्री अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत बिजली निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार सहित महत्वपूर्ण उपयोगिता केन्द्रों और औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

यूपी में 206 पीपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ में तैनात अफसर भी बदले, तीन पीसीएस के भी ट्रांसफर

(जीएनएस)।

लखनऊ, डीजीपी मुख्यालय ने बृहस्पतिवार को डिप्टी एसपी रैंक के 206 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। लखनऊ में तैनात करीब एक दर्जन डिप्टी एसपी को भी बदला गया है। वहीं, तीन पीसीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर भेजा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात विकास कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री सुरक्षा भेजा गया है। गोरखपुर में तैनात उदय प्रताप सिंह द्वितीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ में तैनात सतीश कुमार राय को मेरठ में पीएसी की छठवीं वाहिनी भेजा गया है।

इसी तरह राजधानी में सहायक

पुलिस आयुक्त अभय कुमार मल्ल को बलरामपुर भेजा गया है। महोबा में तैनात गौरव उपाध्याय और अंबेडकरनगर में तैनात शुभम कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए राजेश कुमार सिंह को अब लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है।

ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की और हाल के दिनों में भारत-ब्रिटेन की साझेदारी के

अधिक प्रगाढ़ होने की सराहना की, जिससे दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-ब्रिटेन विजन 2035 साझेदारी का मार्गदर्शन करता रहेगा और वैश्विक भलाई के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: "ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर से मिलकर प्रसन्नता हुई। हाल के दिनों में भारत-ब्रिटेन साझेदारी घनिष्ठ होना सराहनीय है।

लखनऊ बना देश का नंबर-1 सोलर जिला, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास, कई श्रेणियों में मिला पहला स्थान

देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है.

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित "पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह" में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में परचम लहराया है. यूपी को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान मिला, जिससे स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है.

पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देशभर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने "टॉप थ्री स्टेट इंस्टॉलेशन" श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया. इस श्रेणी में गुजरात पहले स्थान पर रहा. उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण है.

जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया. लखनऊ में कुल 1,02,596 सोलर इंस्टॉलेशन किए गए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नागपुर में 89,255 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए. यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के तेजी से विस्तार को दशार्ती है.

राज्यवार "वेरी हाई कंज्यूमर बेस" श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ. इसके साथ ही सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक सोलर इंस्टॉलेशन और अधिकतम वेंडर रजिस्ट्रेशन जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इन उपलब्धियों का श्रेय पीएम और सीएम को दिया. कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी. सौर ऊर्जा न सिर्फ प्रदूषण मुक्त बिजली उपलब्ध कराती है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सौर ऊर्जा क्रांति का अग्रदूत बनकर उभरा है.

यह उपलब्धि प्रदेश वासियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.

निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी , पंजाब की भगवंत मान सरकार का स्वास्थ सम्बंधी बड़ा ऐलान

(जीएनएस)।

लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर ढंग से पहुंचाने और सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भगवंत मान सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 और मेडिकल प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही योजना का दायरा बढ़ाकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह फैसला राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ईँद्दंल्लȥ टंल्लल्ल

पंजाब के अनगिनत परिवारों के लिए अस्पताल जाना अक्सर लंबी कतारों, भीड़-भाड़ वाले वार्डों और इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करना माना जाता है। इस बोझ को कम करने के उद्देश्य से

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और व्यापक बनाते हुए उन 17 मेडिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराने की अनुमति दे दी है, जो पहले केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित थीं।

इस फैसले से केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाओं की सूची और छोटी हो गई है और अब लाभार्थियों को काफी बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इससे खासकर उन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं या सरकारी अस्पतालों पर अधिक मरीजों की निर्भरता है। उन्होंने कहा, "इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव घटेगा, प्रतीक्षा समय कम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।"

नई स्वीकृत प्रक्रियाएं विभिन्न मेडिकल विशेषताओं से संबंधित हैं, जिससे लोगों को भीड़-भाड़ वाले बड़े अस्पतालों में परेशान होने की बजाय अपने घर के नजदीक ही इलाज मिल सकेगा।

बंगाल में 'खेला'! 60 विधायकों की बगावत के बाद अब ममता की 'दिल्ली टीम' खतरे में? क्या 28 सांसद भी बदलेंगे पाला

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। पिछले 15 सालों तक बंगाल की सत्ता पर एकछत्र राज करने वाली ममता बनर्जी के पैर के नीचे से अचानक सियासी जमीन खिसक गई है। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभी पार्टी संभल भी नहीं पाई थी कि 24 घंटे के भीतर वो सब कुछ हो गया जिसकी कल्पना खुद ममता दीदी ने भी नहीं की होगी।

जिस बागी विधायक को ममता बनर्जी ने तीन दिन पहले गुस्से में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी नेता ने आधी से ज्यादा टीएमसी तोड़ दी। टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों का समर्थन जुटाकर वह विधानसभा में 'नेता प्रतिपक्ष' की कुर्सी पर बैठ गया है। अब सबसे बड़ा डर यह है कि विधानसभा के बाद क्या ममता की 'टीम दिल्ली यानी उनके सांसदों में भी

बड़ी टूट होने वाली है? आइए इस पूरे सियासी बवंडर का आसान भाषा में पोस्टमार्टम करते हैं।

03 जून की शाम बंगाल की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गई। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने 58 विधायकों के साथ विधानसभा स्पीकर रथींद्र बसु के सामने परेड की। बाद में दो और विधायकों ने उन्हें समर्थन दे दिया, जिससे यह संख्या 60 तक पहुंच गई। लोकतंत्र के गणित के हिसाब से स्पीकर ने बिना देर किए ऋतब्रत बनर्जी को मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी और उन्हें विधान भवन में आधिकारिक कमरा भी अलॉट कर दिया।

ममता गुट का पलटवार: ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता कुणाल घोष ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि जो विधायक खुद पार्टी से निकाला जा चुका हो, वह टीएमसी विधायक दल का नेता कैसे बन सकता है? उन्होंने दावा किया कि कई विधायकों के दस्तखत दोनों गुटों की चिट्ठी पर हैं।

कानूनी लड़ाई की तैयारी: टीएमसी का आधिकारिक गुट अब स्पीकर के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि बागी गुट ने विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया है।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि दीदी के सबसे भरोसेमंद विधायक ही उनके खिलाफ खड़े हो गए? इस बगावत की स्क्रिप्ट के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर का ही एक नाम है- अभिषेक बनर्जी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और विधायकों का साफ कहना है कि यह बगावत ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की तानाशाही के खिलाफ है।

सम्पादकीय

भय पैदा कर जीतने की चाह

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि मोदी सरकार मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर घबराई हुई है और अपने तंत्र के भीतर से ही घिर चुकी है। पाटी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि असली समस्या यह है कि देश में निजी कम्पनियों का निवेश बेहद कम है जबकि कम्पनियों की कमाई रिकार्ड ऊंचाई पर है। उनका आकलन है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी वंपनियों के निवेश की दर में बहुत गिरावट आई है। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस के यह अर्थशास्त्री नेता इतना भयानक माहौल इस आधार पर बना रहे हैं कि एक मीडिया चैनल ने दावा किया है कि केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है जिसके तहत विदेशी निवेशकों यानि एफडीआई द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश पर लगने वाले 17.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

दरअसल कांग्रेसी अर्थशास्त्री जयराम रमेश ने अपनी डर बेचने की दुकान को चमकाने के लिए एक मीडिया टीवी चैनल की रिपोर्ट को आधार बना तो लिया किन्तु उन्होंने ऐसा कोई तार्किक आधार नहीं दिया जिससे कि उनकी बातों पर भरोसा किया जा सके। आयकर अधिनियम में बदलाव की बात कहां से आ गई? समझ से बाहर की बात तो यह है कि एक केन्द्रीय मंत्री रह चुके व्यक्ति को या तो सूचना का कोई ठोस आधार देना होता है या फिर विमर्श स्थापित करने के लिए वुछ ऐसे तर्क देने पड़ते हैं जो भले ही गलत हों किन्तु वे लगें बिल्वुल सच।

वास्तविकता तो यह है कि जयराम की पाटी बिल्वुल वामपंथी अवतार में है। इसलिए वह ऐसा दावा करने से पहले कि सरकार पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करने जा रही है, यह नहीं सोचा कि कोई भी सरकार इस वक्त ऐसा वुछ भी करने का खतरा नहीं ले सकती जिससे राजकोषीय घाटा बढ़े। जयराम को इस बात से बहुत एतराज है कि देश की वंपनियां लाभ तो खूब कमा रही हैं किन्तु देश में पूंजी निवेश नहीं कर रही हैं। सच तो यह है कि जयराम रमेश जैसे वुछ अर्थशास्त्रियों ने डर का जो अपना शोरूम सजा रखा है उस पर भरोसा करने वालों की लगातार संख्या कम हो रही है। सांख्यकीय और तार्किक आधार दिए बिना आंय-बांय-सांय बोलने से कोई भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का अनुमान नहीं लगा रहा है। जो बात जयराम रमेश जानते हुए भी छिपा रहे हैं वह यह है कि भारतीय कम्पनियां इस वक्त देश के रक्षा उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्र, सड़क निर्माण, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट और बंदरगाह निर्माण में पूंजी निवेश नहीं बल्कि पूंजी झोंक रहे हैं। उक्त क्षेत्रों में सरकार कम और निजी वंपनियां ज्यादा पूंजी लगा रही हैं। यही कारण है कि वुछ ही दिनों में भारतीय निजी वंपनियां निर्माण के क्षेत्र में चीन, साउथ कोरिया, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी की वंपनियों से आगे निकल चुकी हैं। अब चूंकि पाटी की वामपंथी विचारधारा की एसओपी के तहत ही बोलना भी है और सरकार की आलोचना भी करनी है इसीलिए एक अर्थशास्त्री जयराम रमेश तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं जो मात्र राजनीतिक उद्देश्य के लिए अर्थशास्त्र के प्रति अनिभिज्ञता एवं अनिच्छा रखने वालों को बहकाया जा सके। सच यह है कि वुछ अंतर्राष्ट्रीय अस्थाईं बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला किन्तु अर्थव्यवस्था कदापि कमजोर नहीं हुईं है।

गोरखपुर लौट चुके थे योगी, तभी आया अमित शाह का फोन और बदल गया सब कुछ, सीएम बनने की वो कहानी

(जीएनएस)।

आज योगी आदित्यनाथ, वो नाम है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को नई पहचान दी और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने पर पूरा जोर लगा दिया है। 'योगी नीति' का असर यह है कि उसका प्रभाव दूसरे राज्यों तक भी जाता है।

गोरखपुरः मंदिरों के परिसरों में गोरक्षपीठाधीश्वर का योग और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी वो शख्सियत जिनके नाम से गुंडे-माफिया कांपते हैं, जिनकी नीति पूरे देश में हिट है और जिनका मॉडल हर राज्य अपनाना चाहता है। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ अपने धर्म का कर्तव्यनिष्ठा से पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति का वो नाम बन चुके हैं कि लोग उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री कहते हैं।

5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ आज कॉमरेड होते, अगर उनके जीजा की चली होती। योगी आदित्यनाथ का मन स्कूल के दौर से ही सियासत में लगना शुरू हो चुका था। वे एबीवीपी के सदस्य बने और छात्रसंघ चुनाव के दौरान सचिव पद के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर पड़े। वे इस चुनाव में हार चुके थे। दिलचस्प यह था कि अजय सिंह बिष्ट की बहन के देवर यानी रिश्ते में जीजा लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य हुआ करते थे। वे चाहते थे कि युवा अजय एसएफआई ज्वाइन करे, लेकिन उसी दौरान अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात एबीवीपी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। उन्हीं के कहने पर अजय सिंह बिष्ट ने एबीवीपी ज्वाइन कर ली।

विदेश जाने वाली टीम में योगी का नाम

2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। महीनों कड़ी मेहनत, प्रदेशभर के दौरे के बाद जब चुनाव प्रचार और वोटिंग खत्म हो चुकी थी, योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते का ब्रेक लेना चाहते थे। उन्हें विदेश जाने का ऑफर भी मिल चुका था, क्योंकि वे उस समय एक सांसद थे। यह ऑफर उन्हें विदेश मंत्रालय की टीम ने दिया था, जो स्पेन जाने वाली थी। दिलचस्प यह था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस टीम के दौरे से योगी आदित्यनाथ का नाम निकाल दिया था। योगी आदित्यनाथ को शायद कुछ अंदाजा नहीं था कि उनका नाम क्यों बाहर किया गया। अब वे गोरखपुर जाने का अपना प्लान बना चुके थे, लेकिन वक्त उनके लिए कुछ और तय कर चुका था।

सुषमा स्वराज का फोन योगी के पास आया

चुनाव नतीजे आने थे और भाजपा पूरी तरह आश्वस्त थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपाइयों को पछाड़कर वह सत्ता पर काबिज होने में सफल होगी। उधर, योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर निकलने से पहले उनके पास एक फोन आया

और यह फोन उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश योगी तक पहुंचाया था। तब भी योगी को अंदाजा नहीं था कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सोचा जा रहा है।

अचानक योगी के पास अमित शाह का फोन आया

11 मार्च 2017 को घोषित हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। कुल 403 सीटों में से भाजपा ने अकेले 312 सीटें जीतीं और सहयोगियों समेत कुल 325 सीटें हासिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर अनेक नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उठने लगे थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत पीछे था। इधर, योगी भी गोरखपुर लौट चुके थे, तभी उन्हें अमित शाह का फोन आया, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली उपस्थित होने के लिए वे चार्टर्ड की व्यवस्था कर चुके थे और तय बातचीत के हिसाब से योगी भी दिल्ली पहुंच गए।

योगी ने खुद किया खुलासा

18 मार्च की सुबह योगी की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से उनके आवास पर हुई। यह वह मुलाकात थी, जहां अमित शाह बता चुके थे कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, अमित शाह ने सीएम योगी से यह बात अभी गुप्त रखने के लिए बोल दिया था। उत्तराखंड में नई सरकार गठित हो रही थी, उसी बीच लखनऊ में सीएम चेहरे पर मंथन था। भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित हुआ। पूरी कहानी का खुलासा पहली बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में किया था।

गोरखनाथ मंदिर में संत समाज की बैठक

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों से महीनों पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिख चुका था। याद हो कि मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत समाज की चिंतन बैठक हुई थी। कहा जाता है कि इसी बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया था। फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलने पर केंद्र के लिए यह फैसला लेना और भी आसान हो चुका था।

गुरु महंत अवैद्यनाथ ने दिलवाया टिकट

योगी आदित्यनाथ को सही मायने में राजनीति की राह पर गुरु महंत अवैद्यनाथ ने पहुंचाया। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में छात्रों का एक दुकानदार से झगड़ा हुआ था। यह योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। दुकानदार के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था और उस समय विरोध-प्रदर्शन में योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व संभालने का अवसर मिल चुका था। यहां से वे 'एंग्री यंग मैन' बन चुके थे और छात्रों के बीच मजबूत छवि बन चुकी थी। इस झगड़े के बाद सुर्खियों में आए युवा योगी आदित्यनाथ को अवैद्यनाथ ने उसी गोरखपुर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाया, जहां से वे खुद चार बार सांसदी जीत चुके थे।

26 साल की उम्र में सांसद बने योगी

अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर योगी आदित्यनाथ ने साल 1998 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण व हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बनाया। परिणामस्वरूप 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही विजयी रहे।

योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन मॉडलः बीमारू राज्य से आर्थिक शक्ति बनने तक का सफर

उत्तर प्रदेश का बदलाव प्रबंधन की बड़ी कहानी है और इसीलिए आज आईआईएम के शोधार्थी 'यूपी मॉडल' पर शोधपत्र लिख रहे हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है।

किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? यह एक गंभीर सवाल है और लोग इसका जवाब अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग ही देंगे। लेकिन, संदर्भ उत्तर प्रदेश का हो तो इसका सही जवाब है-विजन। किसी भी राज्य के विकास के लिए स्पष्ट विजन का होना जरूरी है। ऐसा न हो तो संसाधन बिखरते हैं, ऊर्जा का सही उपयोग नहीं पाता और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। 2017 में जब एक भगवाधारी संन्यासी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, कारपोरेट जगत से लेकर सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि क्या वह राज्य को विकास की राह पर ले जा पाएंगे? ऐसा राज्य जहां माफिया और अपराधियों की तूती बोलती हो, निवेशक आने से घबराते हों और जिसकी पहचान बीमारू के रूप में होती हो। लोगों के मन में यह प्रश्न उठना सहज ही था, क्योंकि प्रबंधन के स्तर पर राज्य की चूलें हिली हुई थीं। लोगों के प्रश्नों का जवाब उचित प्रबंधन ही दे सकता था और उसके बाद से अब तक का समय यदि इसकी मिसाल बना तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन ही था।

विजन का सही एग्जिक्यूशन

कारपोरेट जगत में एक वाक्य बहुत कॉमन है- ह्यमैनेजर काम सही करता है, लीडर सही काम कराता है।ह्ल यह योगी आदित्यनाथ की प्रबंधकीय दृष्टि ही थी कि उन्होंने सबसे पहले सही काम तय किए और इसे सही तरीके से करने की जिद पकड़ी। मूल सिद्धांत यह कि कानून का राज ही विकास की राह है। यह उनका एक रणनीतिक घोषणापत्र था, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को एक दिशा दी, एक उद्देश्य दिया। साथ ही एक कसौटी भी रखी जिसमें हर नीति, हर निर्णय और हर अधिकारी को परखा जा सके। विजन में ऐसी स्पष्टता हो तो एग्जिक्यूशन की धार अपने आप तेज हो जाती है। बीते नौ सालों में समावेशी विकास की महागाथा, विश्वस्तरीय आयोजन और 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, यह विजन के सही एग्जिक्यूशन से ही आए। इसीलिए योगी आज एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनके फैसले केस स्टडी के रूप में प्रबंधकीय संस्थानों और छात्रों के लिए रुचि का विषय हैं।

जीरो टॉलरेंस बना ब्रांड पोजीशनिंग टूल

योगी सरकार का लक्ष्य था कि बीमार पड़े राज्य को पुनर्जीवित किया जाए। कारपोरेट जगत में इस प्रक्रिया को ह्यटर्नअराउंडह्ल कहते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। पुरानी जड़ें उखाड़ने से लेकर पुराने प्रशासनिक ढांचे तोड़ने थे। उन लोगों को भी बदलना था, जो वर्षों से ह्ययही होता आया हैह्ल की मानसिकता में जी रहे थे। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी ही थी, जिसमें पूरा तंत्र जड़ हो चुका था। न कोई जवाबदेही थी और न ही कोई संस्कृति। उत्तर प्रदेश की पहचान ह्यदंगा प्रदेशह्ल के रूप में थी और यह केवल एक छवि नहीं थी, यह अभिशाप था जो युवाओं को पलायन के लिए बाध्य कर रहा था तो उद्यमियों को आने से रोक रहा था। ऐसे में राज्य की अलग पहचान तभी हो सकती थी जब पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर राज्य को ब्रांड बनाया जाए।

इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने ह्याजीरो टॉलरेंसह्ल नीति को एक ह्यब्रांड पोजीशनिंग टूलह्ल के रूप में इस्तेमाल किया। बुलडोजर ने अपराधियों के हौसले तोड़े तो माफिया के खिलाफ अभियान ने सीधा संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। पूरी कठोरता से इस फैसले के क्रियान्वयन ने देश के उद्योग जगत को स्पष्ट ह्यमार्केटिंग सिग्नलह्ल दिया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। परिणाम राजस्व की बड़ी उछाल के रूप में सामने आया और आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तो यह यहां के प्रबंधन मॉडल की सफलता का परिणाम है।

कुशल सीईओ जैसी कार्यशैली

प्रबंधन में विजन और ब्रांडिंग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है- एग्जिक्यूशन। व्यक्तिगत निगरानी और समय-सीमा के प्रति अटल प्रतिबद्धता। हर परियोजना की डेली मॉनीटरिंग, डैशबोर्ड रिव्यू और स्वयं मुख्यमंत्री की देर रात तक चलने वाली समीक्षा बैठकें, यह किसी स्टार्टअप के कुशल व मेहनती ह्यसीईओह्ल की कार्यशैली नजर आती है। जब सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति खुद जवाबदेह हो, तो पूरा सिस्टम उत्तरदायी हो जाता है। 2025 का महाकुंभ इस एग्जिक्यूशन की क्षमता का सबसे बड़ा और सबसे दृश्यमान प्रमाण था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का एक स्थान पर आना, मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और भीड़ प्रबंधन का प्रयोग था। परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, हर विभाग को एक साथ-एक लय में चलाना, यह तब ही संभव है जब ह्यसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोलह्ल व्यवहार में जीवित हो। महाकुंभ की सफलता ने प्रबंधन का ऐसा इतिहास लिखा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी दौड़े चले आए।

ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी

एक और पहलू है जिसे अनदेखा करना असंभव है- ह्यब्लू ओशन स्ट्रेटेजीह्ल इस स्ट्रेटजी में आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक नया और अछूता बाजार बनाते हैं, जहां कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब सभी राज्य एक ही तरह की नीतियां अपना रहे थे, उत्तर प्रदेश ने ह्यवन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्टह्ल (ओडीओपी) और बाद में ह्यवन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीनह्ल (ओडीओसी) जैसे नवाचार किए। ओडीओपी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा आधार बन गया। इस नीति ने लाखों कारीगरों को न केवल आजीविका दी, बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी और यही किसी भी सफल संगठन की ह्यएचआर पॉलिसीह्ल का सार होता है।

शोध का विषय बना यूपी मॉडल

किसी भी गंभीर संकट में प्रबंधन की असली परीक्षा होती है। उत्तर प्रदेश ने कोविड लहर में यह परीक्षा दो बार दी। ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य ढांचे की सीमाएं और लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी, इन सबके बीच जो प्रशासनिक प्रतिक्रिया सामने आई, वह ह्यइंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटरह्ल के रूप में थी। जिला स्तर पर निगरानी, ऑक्सीजन वितरण की रियल-टाइम ट्रैकिंग, दवाओं की उपलब्धता, यह सब उसी ह्यडैशबोर्ड गवर्नेंसह्ल का विस्तार था जो इस सरकार की पहचान बन चुका है।

उत्तर प्रदेश का बदलाव प्रबंधन की बड़ी कहानी है और इसीलिए आज आईआईएम के शोधार्थी ह्ययूपी मॉडलह्ल पर शोधपत्र लिख रहे हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। यह किसी राज्य के लिए सामान्य बात नहीं है। भगवा कपड़ों में एक संन्यासी का सीईओ रूप सभी को प्रभावित कर रहा है। योगी ने सिद्ध किया है कि नेतृत्व की कोई पोशाक नहीं होती और न ही इसके मूल में कोई पृष्ठभूमि होती है। जनता के प्रति प्रतिबद्धता निष्कपट हो, तो मठ से निकला एक संन्यासी भी देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य का सबसे सफल ह्यटर्नअराउंड सीईओह्ल बन सकता है।

'कपड़े हो गए छोटे', नसीहत देते ही हुईं ट्रोल, परेशान कंटेंट क्रिएटर ने उठाया बड़ा कदम, कौन हैं अनीता बिश्नोई

(जीएनएस)।

डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स रील्स और वीडियो शेयर कर पॉपुलर हो रहे हैं और उनका चेहरा इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जहां लोकप्रियता मिलती है, वहीं कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर को आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है।

ऐसा ही कुछ इंस्ट्राग्राम प्लेटफार्म की कंटेंट क्रिएटर अनीता बिश्नोई के साथ हुआ है। जिन्होंने एक वीडियो के जरिए महिलाओं के पहनावे और बदलती जीवनशैली पर चंद लाइनों के जरिए अपनी राय रखी लेकिन उन्हें नसीहत देना बहुत भारी पड़ गया। जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन हैं अनीता बिश्नोई?

क्या है पूरा मामला?

अनीता का "कपड़े हो गए छोटे शर्म कहां से आए..., रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहां से आए..." वीडियो

देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने अनीता की बात का समर्थन किया, जबकि कई यूजर्स ने इनकी आलोचना करते हुए जमकर ट्रोल करने लगे।

"छोटे हो गए कपड़े..." पर जमकर होने लगी आलोचना तो?

लगातार ट्रोलिंग व आलोचना से अनीता बहुत परेशान अनीता ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी बात रखी और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे कोई शिकायत है तो सामने आकर बात करे, क्योंकि "कानून अपना काम करेगा।"

सोशल मीडिया पर अनीता इतना परेशान हो गई कि उन्होंने जहर खा लिया। पति दिनेश बिश्नोई ने बताया वो घर से बहार थे तभी उन्हें पता चला अनीता इंस्टाग्राम लाइव थीं और एक अन्य इन्फ्लुएंसर पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही थीं। तभी बेटे ने फोन पर बताया कि अनीता ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। पति ने बताया कि परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही थीं। उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।

परिवार ने उन्हें तुरंत जोधपुर के एमडीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां आईसीयू में भर्ती किया गया। अस्पताल के अनुसार, वह खतरे से बाहर व स्थिर हैं, पर डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं।

कौन है अनीता बिश्नोई?

अनीता बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली साधारण सी शादीशुदा घरेलू महिला हैं। इनके पति का नाम दिनेश है और इनका एक बेटा भी है। अनीता सोशल मीडिया पर राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में ये नजर आती हैं। कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर अनीता आमतौर पर फैशन, लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट बनाती हैं। अनीता के सोशल मीडिया पर दस लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

'हर शहर एक जंगल है', कौन है शर्वरी वाघ ? जिसे देखकर बोले बॉबी- 'हसीना दमदार, पैसा वसूल'

(जीएनएस)।

हिंदी सिनेमा के चॉकलेटी स्टार से खतरनाक खलनायक बनकर लोगों का दिल चुराने वाले बॉबी देओल इन दिनों अपनी फिल्म 'Alpha' को लेकर लोगों के बीच सुर्खियां बने हुए हैं। फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी लेकिन इसके ट्रेलर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इसके पीछे वजह है दो हसीनाएं जिनके एक्शन और अदाएं देखने के बाद बॉबी देओल एकदम चकित रह गए, आपने सही समझा हम यहां पर बात कर रहे हैं आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की।

आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ दोनों इस फिल्म में एक्शन करते दिखेगी, ट्रेलर में दोनों का कातिलाना अंदाज देखकर दर्शक अभी से सीटियां बजा रहे हैं। आलिया तो अक्सर अपने किरदारों से लोगों को चकित करती आई हैं लेकिन शर्वरी वाघ का धांसू अंदाज भी लोगों को पानी-पानी कर रहा है।

आपको बता दें कि बहुत कम समय में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली शर्वरी वाघ ने अपने करियर की शुरूआत सहायक निर्देशक के तौर पर

की थी लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनेत्री बना दिया।

शर्वरी वाघ के नाना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे

14 जून 1997 को एक मराठी परिवार में जन्मी शर्वरी वाघ का संबंध एक मजबूत सियासी परिवार से हैं, दरअसल उनके नाना मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शर्वरी वाघ की मम्मी का नाम नम्रता वाघ है जो कि एक आर्किटेक्ट हैं और उनके पापा का नाम शैलेश वाघ है, जो कि एक बिल्डर हैं। उन्होंने 2020 में Amazon Prime की सीरीज 'The Forgotten Army -Azaadi Ke Liye' से सनी कौशल के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी।

Alpha 'के साथ धमाल मचाने को तैयार Sharvari

शर्वरी ने यश राज फिल्म्स (YRF) की क्राइम कॉमेडी फिल्म 'Bunty Aur Babli 2' से फिल्मों में डेब्यू किया। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 'Best Female Debut' का Filmfare Award और 'Star Debut of the Year - Female' का IIFA Award मिला था। इसके बाद उन्होंने 'मुंज्या बेला', 'महाराज विराज', 'वेदा वेदा', जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और इस वक्त वो 'Alpha' के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं।

बॉबी देओल ने क्या-क्या कहा?

बॉबी देओल ने 'अल्फा' की जोरदार तारीफ करते हुए इसे एक स्टाइलिश और हाई-एनर्जी मसाला एंटरटेनर बताया है। उन्होंने कहा कि 'मैं हर दिन शूटिंग पर जाने के लिए उत्साहित रहता था क्योंकि सेट पर हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प और रोमांचक होता था। कलाकारों और तकनीकी टीम के बीच हर दिन आत्मीयता और गर्मजोशी महसूस होती थी, जिससे शूटिंग का माहौल बेहद ही कूल रहता था, जिसका क्रेडिट निर्देशक शिव रवैल को जाता है।' इसके बाद उन्होने आलिया और शर्वरी की तारीफ करते हुए दोनों को दमदार बताया।

'पूरी तरह से मसाला टाइम पैसा वसूल फिल्म होगी अल्फा'

उन्होंने कहा कि 'आलिया और शर्वरी को एक बड़े एक्शन स्पेक्टेकल के केंद्र में देखना भी बेहद रोमांचक था। दोनों ने अपने किरदारों के लिए जबरदस्त समर्पण और एनर्जी दिखाई, जिसने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के अनुभव को और भी खास बना दिया, दोनों कमाल हैं और दोनों का किरदार और अभिनय बेहद दमदार है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को भरपूर प्यार देंगे, ये पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्म होगी।'

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लखनऊ में सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर हो गई मौत

(जीएनएस)।

लखनऊ। विकासनगर सेक्टर सी में बुधवार देर रात सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर 52 वर्षीय संदीप सिंह ने शराब के नशे में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिवारजन व पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो जमीन पर पड़े हुए थे।

उन्हें उठाकर ट्रामा सेंटर ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर विकासनगर आलोक सिंह ने बताया कि लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है।आत्महत्या का कारण पता लगाया जा रहा है।

इंस्पेक्टर ने बताया कि सेक्टर सी के सबोली में संदीप सिंह पत्नी व दो बेटियों के साथ रहते थे। निजी कंपनी में सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर थे।

मृतक के भाई ने बताया कि संदीप बहुत ज्यादा शराब पीने के लती थे। बुधवार की रात करीब दस बजे नशे की हालत में घर पहुंचे और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। कुछ देर बाद संदीप के कमरे से आवाज आई तो देखा कि उन्होंने कनपटी में लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली।

लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हैं। यह देख चीखपुकार मच गई। पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। परिवारजन ने पड़ोसियों की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को सूचना दी।

इंस्पेक्टर ने बताया कि धटना स्थल पर पहुंच कर फारेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। साथ ही लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया है।

परिवारजन से गोली मारने के कारण पूछा गया तो कोई उचित जवाब नहीं मिला। इस पर उनकी कंपनी के लोगों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

टीजीटी परीक्षा 2026; लखनऊ में पांच 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे एग्जाम

आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी परीक्षा 2026) में फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 'मुन्ना भाई' को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों के बारे में लखनऊ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हुसैनगंज स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में जौनपुर निवासी राजेश प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी अभ्यर्थी विजय प्रताप सिंह की जगह पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पता चला है कि यह आरोपी फर्जी आधार कार्ड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों की मदद से परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा गया था.

आरोपी के पास से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक व एक कार बरामद हुई है.

महानगर स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी मन्तेश सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह प्रयागराज निवासी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में यह बात निकल के सामने आई है कि उसने पांच लाख रुपये के बदले सॉल्वर बनकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था. इस काम के लिए इसे पांच हजार रुपये एडवांस मिले थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र की प्रति, मोबाइल फोन व कैश बरामद किया है.

नाका हिंडोला स्थिति डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रयागराज निवासी रंगबहादुर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अभ्यर्थी अवध राज यादव के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है. रंगबहादुर को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अभ्यर्थी अवध राज यादव को भी गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.

अमीनाबाद के विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज से राम मनुज नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फरुर्खाबाद निवासी अभ्यर्थी जितेंद्र सिंह यादव की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा था. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के दौरान उसकी मुलाकात पंकज नामक हुई थी. पंकज यादव ने ही उसे फर्जी दस्तावेज दिए थे और पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार किया था.

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 300 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला, ईडी ने शुरू की जांच, LDA से मांगी फाइल

(जीएनएस)।

लखनऊ : गोमती नगर विस्तार इलाके में हुए करीब 300 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू कर दी है. ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अर्जन विभाग से इस घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज तलब किए हैं. इसके बाद एलडीए दफ्तर में हिमालय सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं. अधिकारी रिकॉर्ड जुटाने में लगे हैं.

मामला गोमती नगर विस्तार इलाके में समिति के नाम पर जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ जमीन दलालों और उनके कारिंदों ने मिलकर फजीर्वाड़ा किया. दिवंगत भूमिया दिलीप सिंह बाफला से जुड़ा यह मामला है. जमीनों की हेराफेरी कर अवैध तरीके से लाखों रुपये कमाए गए. इन जमीनों की असली कीमत को छिपाकर कम दाम पर रजिस्ट्री कराई गई और बाद में ऊंचे दाम पर बेच दिया गया.

रसूखदारों को दी गई जमीन : जिन लोगों को यह जमीन पात्रता के आधार पर दी जानी चाहिए थी उन्हें न देखकर रसूखदारों को दी गई. ईडी को

शिकायत मिली थी कि इस घोटाले में करोड़ों रुपये का काला धन लगाया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने के लिए ईडी ने अब सीधे एलडीए से दस्तावेज मांगे हैं. मांगी गई फाइलों में जमीन अधिग्रहण से जुड़े कागजात, रजिस्ट्री की कॉपी, आवंटन पत्र और समितियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.

फाइल जुटा रहे : एलडीए के अर्जन विभाग के अधिकारी इन फाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि जैसे ही ईडी को सभी दस्तावेज मिल जाएंगे, उनकी जांच शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में जरूरी कागजात मांगे. हिमालय सहकारी समिति से जुड़े सभी दस्तावेज हम परिवर्तन निदेशालय के हवाले कर देंगे. हमारा इस पूरे मामले में यही रोल है.

दिलीप सिंह बाफिला की हिमालयन (द हिमालयन) सहकारी आवास समिति में मुख्य रूप से गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार के जमीन समायोजन/आवंटन घोटाला शामिल है.

घोटाले की मुख्य बातें : द हिमालयन सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति उनके भतीजे प्रवीण सिंह बाफिला से जुड़ी है. इसके माध्यम से 234 भूखंडों (हिमालयन में करीब 122 और दूसरी में 112) का अनियमित फर्जी समायोजन किया गया. छब्अ की अधिग्रहित जमीन के बदले समायोजन के नाम पर फर्जी सदस्य परिवार, रिश्तेदार आदि, बनाकर प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट कम कीमत पर आवंटित किए गए. तय सीमा से ज्यादा जमीन दी गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

यूपी में बहुमंजिला इमारतों और होटलों में फायर सेफ्टी की होगी जांच, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में लगी भीषण आग की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बहुमंजिली इमारतों, होटलों, कार्यालयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में अग्निशमन सुरक्षा की तैयारियों पर मंथन करेंगे।

दिल्ली अग्निकांड में मृतकों के स्वजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुमंजिली इमारतों में अग्निसुरक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अग्निसुरक्षा विभाग ने गुरुवार को विभिन्न इमारतों का दौरा कर मौके पर आग से सुरक्षा

को लेकर किए गए उपायों की जांच की।

शुक्रवार को होने वाली बैठक में विकास प्राधिकरणों, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अग्निसुरक्षा को लेकर कार्ययोजना के साथ बैठक में शामिल हों।

यह वीडियो भी देखें

वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी बहुमंजिली इमारतों, कार्यालयों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर वहां मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि अग्निसुरक्षा को लेकर तैयार विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अग्निशमन विभाग ने राज्य के होटलों की जांच शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश से तरुण चुग, राजस्थान से अलका गुर्जर, भाजपा की लिस्ट में 11 नेता कौन? इन नामों ने बढ़ाई हलचल

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी (इखढ) ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा से कुल 11 नामों का ऐलान किया है। इस सूची में कई अनुभवी संगठनात्मक चेहरों को मौका मिला है, वहीं कुछ फैसलों ने राजनीतिक गलियारों में नई चचाओं को भी जन्म दे दिया है।

बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अहम राज्यों में बड़े चेहरों पर दांव लगाया है। मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है, जो संगठन में लंबे समय से मजबूत पकड़ रखते हैं। उनके साथ ही एमपी से रजनीश अग्रवाल को भी संसद के उच्च सदन का टिकट दिया गया है।

बात अगर राजस्थान की करें तो यहां का समीकरण सबसे दिलचस्प रहा। काफी समय से चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अलका गुर्जर और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान से इस बार केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा टिकट नहीं मिला है, जिनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है।

इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम ओडिशा से

सामने आया है। बीजेपी ने ओडिशा राज्यसभा उप-चुनाव के लिए देबाशीष सामंतराय को अपना उम्मीदवार बनाया है।

सामंतराय ने हाल ही में 25 मई को बीजू जनता दल (BJD) से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें तुरंत राज्यसभा का टिकट देकर न सिर्फ पुरस्कृत किया है, बल्कि ओडिशा में अपने पैर और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

पूर्वोत्तर पर भी फोकस

भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और मणिपुर से ए. शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। शारदा देवी का नाम खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वह भाजपा की महिला नेतृत्व वाली प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। इन नामों के जरिए पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत करने का संकेत दिया है।

कब होगा मतदान और क्या है संसद का मौजूदा गणित?

चुनाव का पूरा शेड्यूलः राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इसके बाद 9 जून को पर्चों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सभी सीटों पर 18 जून को सुबह से मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर उप-चुनाव होगा।

संख्या बल में कौन कितना मजबूतः वर्तमान में 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अकेले बीजेपी के 113 सदस्य हैं, जबकि एनडीए (NDA) का कुल आंकड़ा 148 तक पहुंच चुका है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां बीजेपी के पास बहुमत का अच्छा आंकड़ा है, जिससे इन सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जून के महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज नेता रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी उच्च सदन में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है।

BJP ने क्या संदेश देने की कोशिश की?

भाजपा की इस सूची को देखें तो साफ नजर आता है कि पार्टी ने संगठन के पुराने और भरोसेमंद नेताओं को प्राथमिकता दी है। साथ ही महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया गया है।

तरुण चुग, अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और ए. शारदा देवी जैसे नाम यह संकेत देते हैं कि भाजपा केवल चुनावी समीकरण नहीं, बल्कि संगठनात्मक निष्ठा को भी पुरस्कृत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अब 18 जून को होने वाले चुनाव के बाद यह साफ होगा कि राज्यसभा में भाजपा और एनडीए की ताकत कितनी और बढ़ती है।

सीबीएसई ने कैसे नाकाम किया साइबर हमला? डीओएस अटैक के बीच चलता रहा री-इवैल्यूएशन पोर्टल, बोर्ड ने कहा-डेटा सुरक्षित

(जीएनएस)।

सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बोर्ड के री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को हाल ही में साइबर हमले का निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तकनीकी टीम ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। इस वजह से पोर्टल की सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और छात्रों का काम लगातार चलता रहा।

बोर्ड के अनुसार हजारों छात्रों ने बिना किसी रुकावट के अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा किए। बढ़ते ऑनलाइन खतरों के बीच यह घटना बताती है कि परीक्षा से जुड़ी डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। उइरए ने भी साफ किया है कि छात्रों का डेटा सुरक्षित है और पोर्टल पूरी तरह सामान्य तरीके से काम कर रहा है।

पोर्टल पर किया गया साइबर हमला

उइरए ने बताया कि उसके री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) साइबर अटैक करने

की कोशिश की गई। ऐसे हमलों में किसी वेबसाइट या सर्वर पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा भेजा जाता है ताकि उसकी गति धीमी हो जाए या वह काम करना बंद कर दे। बोर्ड के अनुसार पोर्टल पर करीब 3.8 मिलियन डेटा पैकेट भेजे गए थे। हालांकि तकनीकी टीम लगातार सिस्टम पर नजर रखे हुए थी। संदिग्ध गतिविधि सामने आते ही सुरक्षा उपाय लागू किए गए और हमले को सफल होने से पहले ही रोक दिया गया।

छात्रों के आवेदन जारी रहे

साइबर हमले के बावजूद पोर्टल पर छात्रों की गतिविधियां सामान्य बनी रहीं। बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार रात तक 56 हजार से अधिक आवेदन वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए प्राप्त हो चुके थे। यह संख्या बताती है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने परीक्षा परिणामों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। कई छात्र अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि कुछ छात्रों ने उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।

किन मामलों में दर्ज कर सकते हैं शिकायत

CBSE पहले ही छात्रों को उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा चुका है। इन कॉपियों को देखने के बाद छात्र अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाते हैं तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि उत्तर पुस्तिका का कोई पेज गायब हो, अतिरिक्त शीट शामिल न की गई हो, स्कैन कॉपी साफ दिखाई न दे रही हो या गलत प्रश्नपत्र सेट के आधार पर मूल्यांकन किया गया हो, तो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी खास उत्तर के पुनर्मूल्यांकन की मांग भी की जा सकती है।

सिस्टम को और मजबूत बना रहा बोर्ड

बोर्ड का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार पोर्टल की निगरानी कर रही है। आवेदन की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े। उइरए ने बताया कि कुछ समय पहले पोर्टल को तकनीकी अपग्रेड के लिए अस्थायी रूप से रोका गया था। इसके बाद सुरक्षा और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाया गया, जिससे सेवाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज हो सकें।

भुगतान के लिए कई विकल्प उपलब्ध

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उइरए ने कई सरकारी बैंकों के पेमेंट गेटवे को अपने सिस्टम से जोड़ा है।

बंगाल में पूर्व मंत्री के भाई स्वरूप बिश्वास गिरफ्तार, क्या लगे हैं आरोप?

(जीएनएस)।

बंगाल से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास के भाई और टीएमसी नेता स्वरूप बिश्वास को न्यू अलीपुर पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। स्वरूप बिश्वास पर जबरन वसूली और छेड़छाड़ जैसे कई बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस को पिछले कुछ समय से कोलकाता के लोकल स्टूडियो इलाकों से स्वरूप बिश्वास के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पीड़ितों का

आरोप है कि स्वरूप बिश्वास काफी समय से टॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डरा-धमका रहे थे और उनसे मोटी रकम वसूल रहे थे। बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रही, उन पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का भी संगीन आरोप लगा है।

पूर्व मंत्री के भाई होने से गर्माई राजनीति

स्वरूप बिश्वास की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने की है। चूंकि वह पूर्व मंत्री अरूप बिश्वास के सगे भाई हैं, इसलिए इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के सियासी हलकों में इस गिरफ्तारी को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है और विरोधी दल भी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

पुलिस स्टेशन में मैराथन पूछताछ जारी

बुधवार देर रात हुई इस अचानक कार्रवाई के बाद पुलिस स्वरूप बिश्वास को थाने ले आई है। फिलहाल, न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में सीनियर अफसरों की मौजूदगी में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी शुरूआती दौर में है और जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं।

मुंबईकर हो जाएं अलर्ट! मानसून में समुद्र दिखाएगा रौद्र रूप, बीएमसी ने जारी किया हाई टाइड अलर्ट

(जीएनएस)।

मुंबई में रहने वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। शहर में मानसून के साथ समुद्र का मिजाज भी काफी खतरनाक होने वाला है। मॉनसून में मुंबई में समुद्र एक नहीं कई बार रौद्र रूप धारण करने वाला है। समुद्र से जानलेवा ऊंची समुद्री लहरें उठेगीं।

गुरुवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जून से सितंबर के बीच 24 बार 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंची हाई टाइड आएगी। ऐसे में मुंबईकरों को समुद्र किनारे जाने से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

16 जुलाई को सबसे बड़ा खतरा

इटउ के अनुसार, इस मानसून का सबसे खतरनाक हाई टाइड 16 जुलाई को आने की संभावना है। उस दिन समुद्री लहरें करीब 4.89 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। इसे देखते हुए

प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट और तटीय इलाकों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। पहली हाई टाइड की शुरूआत 14 जून से 19 जून के बीच होने वाली है।

चार महीनों में 24 बार हाई टाइड का अलर्ट

मानसून के दौरान जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कई बार समुद्र उफान पर रहेगा। BMC के आंकड़ों के मुताबिक जून में 6, जुलाई में 6, अगस्त में 5 और सितंबर में 7 बार 4.5 मीटर से अधिक ऊंची हाई टाइड दर्ज की जाएगी।

समुद्र किनारे सेल्फी और सैर से बचें

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाई टाइड के दौरान समुद्र किनारे घूमने, सेल्फी लेने या पानी के करीब जाने की गलती न करें। तेज हवाएं और ऊंची लहरें हादसों का कारण बन सकती हैं। वहीं मछुआरों को भी विशेष सतर्कता बरतने और मौसम संबंधी सभी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

लखनऊ के 332 गांवों में कृषि जमीन के सर्किल रेट में बंपर बढ़ोतरी, 1 करोड़ प्रति हेक्टेयर पहुंची कीमत

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में जिनके पास कृषक जमीनें हैं उनके लिए खुशखबरी। जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को छोड़कर 332 गांवों में कृषि योग्य जमीनों के डीएम सर्किल रेट सौ से दो सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है।

नई दरों के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कानपुर रोड और बिजनौर रोड के आसपास गांवों में जमीन की दरें एक करोड़ रुपये से लेकर सवा करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई हैं। जिला प्रशासन ने प्रचलित डीएम सर्किल रेट और बाजार दर के बीच अंतर को कम करने के लिए संशोधित दरों का प्रस्ताव दिया था।

सर्किल रेट बढ़ाने के लिए 29 मई को पेश किया गया था प्रस्ताव

संशोधित दरों के लागू होने के बाद जिन गांवों में डीएम सर्किल रेट प्रति हेक्टेयर बीस से चालीस लाख रुपये था वहां पर बढ़कर 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक हो गया है। गुरुवार को आपत्तियों के निस्तारण के बाद संशोधित दरें लागू कर दी गईं।

एक अगस्त 2025 को लखनऊ में

एक दशक से अधिक अंतराल के बाद नया डीएम सर्किल रेट लागू किया गया था। जिसमें शहर से लेकर गांव तक कृषि, आवासीय और व्यवसायिक जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। एक अगस्त को जो दरें लागू की गई थीं उनमें ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र और नगर निगम सीमा में आने वाले गांवों को छोड़कर शेष 332 गांवों में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए 29 मई को प्रस्ताव पेश किया गया था।

तीन जून तक आपत्तियों पर सुनवाई की गई जिसमें कुछ गांवों में दरों में और बढ़ोतरी की गई। एडीएम राजस्व राकेश कुमार सिंह के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर और डीएम सर्किल रेट के बीच काफी अंतर था एसडीएम और उपनिबंधकों के सर्वे में भी कृषि दरों में बाजार मूल्य एवं प्रचलित सर्किल दरों में भिन्नता पाई गई थी। इसी आधार पर दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया।

कुछ प्रमुख सड़कों के आसपास गांवों में दरें

भागू खेड़ा चौराहे से किसान पथ तक गांव - 1.30 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर

जुनाबगंज चौराहे से भागू खेड़ा चौराहे तक - 1.30 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर

बिजनौर रोड से बंथरा तक के सभी गांव - एक करोड़

कानपुर रोड से कटी बगिया मोहान रोड तक सभी गांव - एक करोड़

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास गांव - एक करोड़ रुपये

सदर के पपनामऊ गांव में अकृषक जमीन की संशोधित दरें भी जारी

12 मीटर चौड़ी सड़क पर : 8800 रुपये प्रति वर्ग मीटर

12 से 18 मीटर सड़क पर : 9500 रुपये प्रति वर्ग मीटर

18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर : 10500 वर्ग मीटर

यूपी को एक और हाईस्पीड रेल की सौगात, लखनऊ-कानपुर नमो भारत कॉरिडोर की तैयारी तेज; जानें पूरा अपडेट

(जीएनएस)।

लखनऊ,

लखनऊ-कानपुर के बीच शुरू होने वाली नमो भारत रेल सेवा के काम में तेजी आई है। शासन ने डीपीआर तैयार करने के लिए मंजूरी दे दी। एनसीआरटीसी को जिम्मेदारी दी गई है। हाईस्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत चलाने का काम का काम तेज हो गया है। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अल्टरनेटिव्स एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए छह करोड़ रुपये का बजट पास है। रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) नई दिल्ली को सौंपी गई है।

व्यस्त समय में 10 अतिरिक्त फेरे लगाएगी नमो भारत

एएआर और डीपीआर में नमो भारत रेल सेवा

कॉरिडोर का प्रस्तावित रूट, संभावित स्टेशन, अनुमानित यात्री संख्या, निर्माण लागत, तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय मॉडल का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद परियोजना को अंतिम स्वीकृति और निर्माण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ताकि रेल सेवा का काम जल्द शुरू किया जा सके। पत्र में प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि परियोजना पर

इसको लेकर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने एनसीआरटीसी को पत्र भी भेजा है। आने वाला खर्च लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण और उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से वहन करेंगे।

इस रेल सेवा के शुरू होने के बाद उन लोगों को बहुत राहत होगी जो लखनऊ और कानपुर के बीच रोजाना बड़ी संख्या में नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए आवागमन करते हैं। नमो भारत कॉरिडोर शुरू होने पर यात्रियों को तेज, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्नाव समेत पूरे क्षेत्र में औद्योगिक, व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

गोरखपुर में सिक्सलेन और फोरलेन फ्लाईओवर का एक साथ होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

(जीएनएस)।

गोरखपुर। ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ बने सिक्सलेन और देवरिया बाईपास की तरफ से बन रहे फोरलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण एक साथ होगा। फोरलेन फ्लाईओवर का काम इसी महीने की 20 तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसी महीने दोनों फ्लाईओवर का लोकार्पण हो सकता है। इस बीच, सेतु निगम ने पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ से देवरिया बाईपास की ओर जाने वाले साइड रोड को खोल दिया है। इससे राहगीरों को काफी राहत मिली है।

सेतु निगम ने पिछले महीने ही ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास के आगे पैडलेगंज की तरफ सिक्सलेन फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करा दिया है। फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ ही इसका परीक्षण भी करा लिया गया है। स्वागत द्वार भी लगा दिए गए हैं। माना जा रहा था कि पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा। इसके बाद फोरलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा लेकिन अब दोनों का लोकार्पण एक साथ करने की बात कही जा रही है।

मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

पूर्वांचल के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर और इससे जुड़ रहे फोरलेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। सेतु निगम ने निर्माण की गुणता के साथ ही झटका मुक्त फ्लाईओवर तैयार करने का दावा किया है। दोनों फ्लाईओवर शुरू होने के बाद देवरिया बाईपास, नहर रोड, रुस्तमपुर, महेवा और ट्रांसपोर्टनगर में जाम की समस्या का तो समाधान होगा ही राहगीरों को कम समय में यात्रा पूरी करने का लाभ मिलेगा।

429.49 करोड़ रुपये हो रहे खर्च

ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ बने सिक्सलेन फ्लाईओवर की लंबाई 2.6 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 429.49 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। दोनों फ्लाईओवर शुरू होने से लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और प्रयागराज से आने वाले यात्रियों को शहर के भीतर प्रवेश करने या शहर से होकर लखनऊ, वाराणसी, महराजगंज, देवरिया या कुशीनगर जाने में समय की काफी बचत होगी।

देवरिया बाईपास पर रूट डायवर्ट किया गया

देवरिया बाईपास पर फोरलेन फ्लाईओवर की एक लेन बनाने के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। पहले रूट का डायवर्जन देवरिया बाईपास पर रुस्तमपुर की तरफ था, अब इसे पैडलेगंज की तरफ कर दिया गया है। हालांकि अगल-बगल निर्माण सामग्री रखे जाने के कारण सड़क संकरी हो गई है। इससे आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और पर्यावरण अभियान की समीक्षा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 05 जून, विश्व पर्यावरण दिवस पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में न्यूनतम 05 करोड़ पौधों का रोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृत्व सम्मान और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश भी देता है। पौधों की उपलब्धता, जियो टैगिंग तथा

संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जाए तथा समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में आगामी 08, 09 एवं 10 जून को आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो।

उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने तथा आमजन एवं परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग को रियायती किराये पर विशेष अंतर्जनपदीय बसों के संचालन तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं वैकल्पिक बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

अलका गुर्जर कौन हैं? भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से क्यों बनाया उम्मीदवार, क्या है रणनीति

(जीएनएस)।

बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव अलका गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान की राजनीति में दो दशक से भी अधिक समय से एक प्रमुख जाट नेता रहे हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद, पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा है।

वहीं लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन बीजेपी ने सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाकर बड़ी चाल चल दी है। जानिए कौन हैं अलका गुर्जर और क्यों भाजपा ने इन्हें बनाया राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतारा है?

अलका गुर्जर का जन्म 21 फरवरी 1961 को हुआ। अलका वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय महासचिव के

रूप में कार्यरत हैं और इसके साथ ही दिल्ली में भाजपा की सह-प्रभारी भी हैं। राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहीं अलका गुर्जर ने वर्ष 2013 से 2018 तक बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक (एमएलए) रहीं। इसके बाद उन्हें भाजपा संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उन्होंने प्रदेश स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठनात्मक दायित्व निभाए हैं और पार्टी के कई राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

भाजपा की प्रमुख महिला नेताओं में गिनी जाने वाली अलका गुर्जर के पति डॉ. नाथू सिंह गुर्जर भी पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी में वरिष्ठ संगठनिक भूमिकाओं में थे।

अलका गुर्जर को भाजपा ने क्यों बनाया उम्मीदवार?

अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाना गुर्जर समुदाय में बीजेपी की पहुंच को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही, यह "नारी वंदन" जैसी पहलों के माध्यम से महिला नेतृत्व पर पार्टी के जोर को भी रेखांकित करता है।

ममता के लिए चुनौती पूर्व राज्यसभा सांसद और अब विधायक ऋतब्रत? कितनी है दौलत-कितने केस? पत्नी की आय में 220% उछाल!

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 28 साल बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर पहली बड़ी दरार आ गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद और अब विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने 58 विधायकों के समर्थन के साथ पार्टी के भीतर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है और छुड़ा का कक्ष भी आवंटित कर दिया गया है।

ममता बनर्जी के लिए यह झटका ऐतिहासिक है। एक तरफ पार्टी के संस्थापक के रूप में उनका कद, दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल। ऋतब्रत बनर्जी अब खुद को 'असली TMC' का चेहरा बता रहे हैं। उनकी राजनीतिक सफर, संपत्ति का पूरा ब्योरा, पत्नी दुर्बा सेन की आय में भारी उछाल, क्रिमिनल केस और ममता-अभिषेक के साथ टकराव की पूरी कहानी विस्तार से एक-एक पहलू पर बात करते हैं...

राजनीतिक सफर

15 नवंबर 1979 को कोलकाता में जन्मे ऋतब्रत बनर्जी की उम्र फिलहाल 46 साल है। पिता प्रियभूषण बनर्जी। साउथ पॉइंट हाई स्कूल, आशुतोष कॉलेज से स्नातक और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर्स (2003) किया।

उनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई। वे CPI(M) की छात्र इकाई SFI के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2014 में मात्र 35 साल की उम्र में CPI(M) ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2017 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में CPI(M) से निष्कासित कर दिए गए। 2020 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और INTTUC जैसी ट्रेड यूनियन विंग में सक्रिय रहे। 2026 के चुनाव में उलुबेड़िया पूर्व सीट से विधायक बने।

अब जून 2026 में वे TMC के सबसे बड़े बागी नेता के रूप में उभरे हैं। 58 विधायकों (TMC के कुल 80 में से) का समर्थन दावा करते हुए उन्होंने स्पीकर को पत्र सौंपा। स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष मान्यता दी। बागी गुट ने ममता बनर्जी को 'मुख्य सलाहकार' बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

ममता बनर्जी से रिश्ता:

राजनीतिक, पारिवारिक नहीं

ऋतब्रत और ममता बनर्जी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। पहले CPI(M) में रहते हुए वे ममता के कट्टर आलोचक थे। TMC में आने के बाद करीबी बने, लेकिन 2026 में संगठनात्मक लोकतंत्र, परिवारवाद और अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दबदबे को लेकर असंतोष जाहिर किया। बागियों का कहना है कि हम ममता दीदी का सम्मान देते हैं, लेकिन पार्टी को निजी परिवार की संपत्ति नहीं बनने देंगे।

पत्नी दुर्बा सेन की आय में 220% का उछाल - आंकड़े चौंकाते हैं

2024 के राज्यसभा चुनावी हलफनामे के अनुसार, पत्नी दुर्बा सेन का पेशा Mackintosh Burn Limited में Managing Director और Confidential Assistant है। आय का मुख्य स्रोत सैलरी और ब्याज।

पत्नी दुर्बा सेन की आय (पिछले 5 वर्ष):

2023-24: ₹12,41,340

2022-23: ₹11,85,180

2021-22: ₹1,97,310

2020-21: ₹3,55,250

2019-20: ₹3,87,570

वृद्धि का आंकलन: 2019-20 से 2023-24 के बीच आय में करीब 220% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में आय अचानक बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद लगातार उछाल आया। राजनीतिक विरोधी इसे 'सवालिया' बता रहे हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि प्रोफेशनल तरक्की और निवेश से हुआ है।

ऋतब्रत बनर्जी की खुद की आयः

2023-24: ₹4,75,567

2022-23: ₹14,91,440 (सबसे अधिक)

2021-22: ₹9,66,940

2020-21: ₹5,78,610

2019-20: ₹11,21,080

कुल संपत्तिः लगभग ₹3.44 करोड़

2024 के हलफनामे के अनुसार:

चल संपत्तिः ऋतब्रत के नाम करीब ₹99.20 लाख, पत्नी के नाम करीब ₹1.25 करोड़

अचल संपत्तिः कोलकाता के Salbani Apartments में संयुक्त फ्लैट। ऋतब्रत की हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत करीब ₹91.57 लाख

कुल संपत्तिः लगभग ₹3.44 करोड़

नकदः ऋतब्रत ₹20,233, पत्नी ₹75,600

गाड़ीः पत्नी के नाम Innova Crysta (2021 मॉडल, ₹24.62 लाख कीमत की)

जेवरः ऋतब्रत के पास 15 ग्राम (₹1.10 लाख), पत्नी के पास 350 ग्राम (₹25 लाख)

निवेशः SBI म्यूचुअल फंड, छक्क पॉलिसी, बैंक FD आदि।

देनदारियांः ऋतब्रत पर करीब ₹27.28 लाख (हाउसिंग लोन), पत्नी पर करीब ₹21.08 लाख (हाउसिंग + कार लोन)। सरकारी बकाया (IT, GST आदि) NIL राज्यसभा सचिवालय से No Dues Certificate भी उपलब्ध।

3 क्रिमिनल केस

हलफनामे के अनुसार कुल 3 लंबित आपराधिक मामले, कोई सजा नहीं।

केस 1 (2013): Parliament Street PS, दिल्ली। IPC 186, 353, 147, 149, 341। योजना भवन के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा। चार्जशीट नहीं हुई।

केस 2 (2017): BÔlurghÔt PS, दक्षिण दिनाजपुर। IPC 195अ, 214, 506, 120B, बेल मिली। केस 3 (2017): Balurghat PS। IPC 417, 376(2)(n), 214, 354, 506, 509। एक महिला का शादी के झांसे में संबंध बनाने का आरोप। Anticipatory bail मिली। ऋतब्रत इन आरोपों को राजनीतिक साजिश और ब्लैकमेल बताते रहे हैं।

TMC में बगावत का कारण क्या?

बागी गुट का मुख्य आरोपः अभिषेक बनर्जी का एकाधिकार और परिवारवाद, संगठन में लोकतंत्र की कमी, टिकट वितरण और फैसलों में पारदर्शिता न होना

ऋतब्रत ने कहा कि संख्या बल राज करता है। 80 में से 58 हमारे साथ हैं, जो दो-तिहाई (54) से ज्यादा है। हम दल-बदल कानून से सुरक्षित हैं। उन्होंने ममता से 'मुख्य सलाहकार' बनने की अपील की है।

छक्क की तरफ से कुणाल घोष जैसे नेताओं ने इसे 'पीठ में छुरा' बताया और भाजपा से सांठगांठ का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी मोर्चा इकाइयों को भंग कर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आइए अब समझते हैं कि क्यों छक्क में कथित टूट की तुलना महाराष्ट्र की शिवसेना और NCP संकट से हो रही है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर उभरे विवाद और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी खेमे के दावों की तुलना महाराष्ट्र में शिवसेना (2022) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-उठछ (2023) में हुई ऐतिहासिक टूट से की जा रही है।

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस इन 5 खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज, अगले सीजन से पहले बदल जाएगी टीम?

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों मिली करारी हार के बाद उपविजेता गुजरात टाइटंस (GT) की टीम में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है। आरसीबी ने जहां लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा, वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस फाइनल के दबाव को झेलने में नाकाम रही। इस भारी शिकस्त के बाद टीम कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

राहुल तेवतिया

गुजरात की रिलीज लिस्ट में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम ऑलराउंडर राहुल तेवतिया का है। तेवतिया को टीम ने 4 करोड़ की मोटी रकम पर अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उनका प्रदर्शन इस कीमत के साथ न्याय नहीं कर सका। इस सीजन में उन्होंने 15 पारियों में केवल 190 रन बनाए। इससे पिछले सीजन में भी वे

12 पारियों में केवल 92 रन ही बना पाए थे। मैनेजमेंट उनके 4 करोड़ बचाकर ऑक्शन पर्स को बढ़ाना चाहेगा।

ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड)

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए मशहूर कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स इस सीजन में पूरी तरह फ्लॉप रहे। फिलिप्स ने 5 पारियों में केवल 16.75 की खराब औसत से महज 67 रन बनाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि कप्तान शुभमन गिल ने पूरे टूर्नामेंट में उनसे एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं कराई। ऐसे में उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है।

इशांत शर्मा (कीमत 75 लाख)

37 वर्षीय अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का भविष्य भी अब टाइटंस के साथ सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। बढ़ती उम्र और कम होती रफ्तार के कारण उन्हें आईपीएल 2026 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। टीम अपने 75 लाख के फंड को रीसायकल करने के लिए उन्हें रिलीज कर सकती है।

साई किशोर (बाएं हाथ के स्पिनर)

साई किशोर के लिए यह सीजन बेहद निराशाजनक रहा। वे केवल 2 मैचों में प्लेइंग-11 का हिस्सा बन पाए, जहां उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। गुजरात मैनेजमेंट ने इस बार साई किशोर के मुकाबले मानव सुथार जैसे नए और युवा स्पिनरों पर अधिक भरोसा दिखाया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि साई किशोर को रिलीज किया जा सकता है।

बतौर फिनिशर टीम में शामिल किए गए शाहरुख खान मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सके। उन्हें 5 पारियों में बल्लेबाजी का मौका।

भारत-अफगानिस्तान टेस्ट वर्डकप का हिस्सा क्यों नहीं? आईसीसी का वो नियम जिसके चलते टीम इंडिया को नहीं मिलेंगे अंक

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर रेड-बॉल से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लनपुर में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है। हालांकि, भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ मजबूत टीम उतारी है, लेकिन यह मैच मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के चक्र का हिस्सा नहीं होगा।

इस वजह से नहीं जुड़ेंगे जीत के अंक

अफगानिस्तान के साथ-साथ आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए,

इन टीमों के साथ खेले जाने वाले टेस्ट मैच को केवल एक सामान्य 'द्विपक्षीय मुकाबला' माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा तकनीकी कारण इस सीरीज का फॉर्मेट है। भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला एक स्टैंडअलोन या वन-ऑफ (एकमात्र) टेस्ट मैच है।

आईसीसी के डब्ल्यूटीसी नियमों के मुताबिक किसी भी टेस्ट सीरीज को चैंपियनशिप के अंकों के लिए तभी मान्य माना जाएगा, जब उस सीरीज में कम से कम दो टेस्ट मैच खेले जाएं। चूंकि यह सिर्फ एक मैच की सीरीज है, इसलिए अगर दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी का हिस्सा होतीं, तब भी इस मैच से कोई अंक नहीं मिलता।